

## कार्बन मूल्य निर्धारण और क्यों पर पुनर्विचार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा स्वर्ण मानक के रूप में घोषित, ब्रिटेन के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के पक्ष में बहुत कुछ है। फिर भी, यह उस एक आसन्न नीतिगत साधन को संबोधित नहीं करता है जो भारत के लिए इसके संभावित लाभों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है।

यूके का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (यूके-सीबीएएम), जो सिद्धांत रूप में यूरोपीय संघ (ईयू) के सीबीएएम के समान है, जनवरी 2027 से लागू किया जाएगा। यह इस्पात और एल्युमीनियम जैसे कठिन-से-कम करने योग्य क्षेत्रों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के उत्सर्जनों को कवर करता है, जिसमें उनके उत्पादन में उपयोग की जाने वाली बिजली भी शामिल है। सीबीएएम का दायरा बाद में अन्य उत्पादों तक बढ़ाया जाएगा।

श्री गोयल ने कहा कि भारत सीबीएएम के किसी भी हानिकारक प्रभाव का प्रतिकार करेगा। हालाँकि, कोई भी संभावित कार्रवाई आसन्न लागत प्रभाव के लिए वांछित राहत प्रदान नहीं कर सकती है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसका द्विपक्षीय समझौते में पहले ही समाधान किया जाना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, हाल ही में घोषित अमेरिका-यूरोपीय संघ व्यापार समझौते में, यूरोपीय संघ लचीलेपन के माध्यम से कार्बन-आधारित आयात शुल्क (CBAM) और कंघेरिट स्थिरता से संबंधित अन्य नियमों पर अमेरिका की चिंताओं का समाधान करने पर सहमत हुआ है।

**भारत के निर्यात पर कार्बन-आधारित आयात शुल्क (CBAM) का प्रभाव** मुक्त व्यापार समझौते (FTA) से पहले, एल्युमीनियम और लौह एवं इस्पात के लिए ब्रिटेन की MFN दरें 0-6% के बीच थीं। भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के तहत, भारतीय निर्यात के लिए ये शुल्क शून्य हो जाएंगे। पहली नज़र में, यह भारत के लिए फायदेमंद प्रतीत होता है। लेकिन जनवरी 2027 से, एल्युमीनियम और इस्पात के आयात को ब्रिटेन के कार्बन मूल्य के बराबर होना होगा, जो वर्तमान में लगभग \$66/tCO<sub>2</sub> है, जिसका अर्थ है कि निर्यातकों के लिए लागत में कम से कम 20% से 40% की वृद्धि होगी।

ब्रिटेन का कार्बन-आधारित आयात शुल्क (CBAM) निर्यातक देशों में कार्बन मूल्य निर्धारण के लिए कटौती की अनुमति देता है, जिसमें कार्बन कर या उत्सर्जन व्यापार योजनाओं के तहत भुगतान की गई कीमतें शामिल हैं। भारतीय उद्योग कोयला उपकर



**Prachi Priya**

Mumbai-based economist. Views are personal



**R.V. Anuradha**

Partner, Clarus Law Associates, New Delhi. Views are personal

जैसे शुल्क चुकाता है, नवीकरणीय खरीद दायित्व के अंतर्गत लागत वहन करता है और अब हाल ही में घोषित कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (सीसीटीएस) के तहत एक स्पष्ट कार्बन मूल्य भी निर्धारित करता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि ब्रिटेन सीसीटीएस से परे कटौती की अनुमति देगा या नहीं। सीसीटीएस के संबंध में भी, एक बड़ी चुनौती भारत के अनुमानित कार्बन मूल्य, जिसका अनुमान ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा लगभग 8-10 डॉलर प्रति टन CO<sub>2</sub> लगाया गया है, और ब्रिटेन के कार्बन मूल्य, जो वर्तमान में 66 डॉलर प्रति टन है, के बीच का बड़ा अंतर है।

यूरोपीय संघ के सीबीएएम की तरह, ब्रिटेन का दृष्टिकोण घरेलू उत्पादकों द्वारा भुगतान की गई अंतर्निहित कार्बन कीमत के बराबर ब्रिटेन में निर्यात पर शुल्क लगाने पर केंद्रित है। विशिष्ट क्षेत्रों में, जहाँ ब्रिटेन प्रतिस्पर्धात्मक रूप से पिछड़ा हुआ महसूस करता है, ब्रिटेन के उत्पादकों द्वारा भुगतान की गई कीमत के बराबर मूल्य लगाकर, कार्बन मूल्य का एकतरफा निर्धारण संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और पेरिस समझौते के तहत उत्सर्जन में कमी लाने की बहुपक्षीय प्रतिबद्धताओं को उलट देता है।

सभी अर्थव्यवस्थाओं में एक समान कार्बन मूल्य कभी नहीं हो सकता क्योंकि ऊर्जा मिश्रण, उद्योग संरचना और तकनीकी उपलब्धता एवं व्यवहार्यता के आधार पर विभिन्न देशों में उत्सर्जन अलग-अलग होता है। अक्टूबर 2024 में बहुपक्षीय संस्थानों द्वारा जारी एक संयुक्त रिपोर्ट में कार्बन बाजारों पर अधिक समन्वय का आग्रह किया गया था, जिसमें चेतावनी दी गई थी कि खंडित प्रणालियाँ विकृतियाँ, रिसाव पैदा करती हैं और शुद्ध-शून्य लक्ष्यों को कमजोर करती हैं।

खंडित बाजार केवल अनुपालन लागत बढ़ाएँगे, आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करेंगे और विकास तथा जलवायु लक्ष्यों, दोनों में बाधा डालेंगे। उत्सर्जन मापने के तरीकों को संरखित करने, रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को सुव्यवस्थित करने और हरित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए समर्थन सुनिश्चित करने के लिए एक वैश्विक कार्बन मूल्य निर्धारण समझौता आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2021 में स्तरीय मूल्य निर्धारण के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय कार्बन मूल्य तल (ICPF) प्रस्तावित किया था: निम्न-आय वाले देशों के लिए 25 डॉलर, मध्यम-आय वाले देशों के लिए 50 डॉलर और उच्च-आय वाले देशों के लिए 75 डॉलर। इसी केआधार पर, विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक कार्बन मूल्य निर्धारण में सुचारू परिवर्तन के लिए तीन-चरणीय दृष्टिकोण का प्रस्ताव रखा, जिसकी शुरुआत मूल्य निर्धारण और रिपोर्टिंग के लिए न्यूनतम मानकों से होगी, और इसे क्षेत्रीय प्रणालियों से जोड़ा जाएगा तथा निगरानी और सत्यापन प्रक्रियाओं में सामंजस्य स्थापित किया जाएगा। इसने विखंडन को कम करने और एक एकीकृत वैश्विक प्रणाली की ओर बढ़ने के लिए क्षेत्रीय कार्बन बाजारों (यूरोपीय संघ, चीन, भारत, एशिया के अन्य भागों) को जोड़ने का भी प्रस्ताव रखा।

भारत सरकार के लिए यह आकलन करना महत्वपूर्ण है कि क्या यह मॉडल कारगर होगा और समान विचारधारा वाले विकासशील देशों के साथ तालमेल की संभावना तलाशनी चाहिए। बढ़ते टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं के दौर में, हम विखंडित कार्बन मूल्य निर्धारण को भारी अनुपालन लागतों में बदलने का जोखिम नहीं उठा सकते।

##### राष्ट्रीय कार्रवाई

बढ़ते संरक्षणवाद के बीच, अल्पावधि में वैश्विक सहमति की संभावना कम है। इसलिए भारतीय उद्योग को स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को केवल निर्यात अनुपालन के रूप में नहीं, बल्कि दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता के साधन के रूप में देखना चाहिए। सरकार को विभिन्न अंतर्निहित कार्बन करों को एक एकीकृत कार्बन बाजार ढाँचे में सुव्यवस्थित करके एक सक्षमकर्ता के रूप में कार्य करने की आवश्यकता है। कार्बन-प्रधान क्षेत्रों पर कई करों के बजाय, CCTS के माध्यम से एकल स्पष्ट कार्बन कर के अंतर्गत कठोर उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्यों को लागू करने से कार्बन मूल्य निर्धारण में सुधार होगा, अनुपालन और निगरानी सरल होगी, और हमारे प्रतिस्पर्धात्मकता बनी रहेगी। यह भारत को एक मज़बूत कार्बन मूल्य निर्धारण प्रणाली बनाने की स्थिति में लाएगा, जो भविष्य में एक समेकित वैश्विक कार्बन बाज़ार में शामिल होने में सक्षम होगी। इन कार्बन करों से प्राप्त राजस्व को औद्योगिक डीकार्बोनाइज़ेशन के लिए वापस लगाया जाना चाहिए। वित्त मंत्रालय द्वारा विकसित जलवायु वित्त वर्गीकरण का मसौदा एक और पहल है जो निवेशकों को स्वच्छ तकनीक निवेश को बढ़ावा देने में सक्षम बनाएगी।

ऐसी दुनिया में जहाँ बहुपक्षीय नियमों को कमजोर किया जा रहा है, और द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते समानता सुनिश्चित करने में विफल हो रहे हैं, देश के भीतर सरकार और उद्योग के बीच सक्रिय कार्रवाई ही एकमात्र समाधान है।

## भारत-अमेरिका संबंध: विश्वास साझेदारी को परिभाषित करता है, टैरिफ को नहीं

टैरिफ में व्यापक बढ़ोतरी से भले ही तकलीफ हो, लेकिन भारत-अमेरिका संबंध लचीलेपन, रणनीतिक तालमेल और लोगों के बीच आपसी संबंधों पर आधारित हैं।

DATA POINT	
<b>Mehnaz Ansari</b>	
अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर शुल्क में भारी वृद्धि करने के निर्णय—विभिन्न उत्पादों पर शुल्क दोगुना करके 50% करने—ने भारत में गहरी चिंता और निराशा पैदा की है। दशकों तक एक परिपक्व, बहुआयामी संबंध बनाने के बाद, इस तरह के व्यापक व्यापार उपयोगों को लागू करना एक झटके की तरह लगता है। इसका आर्थिक प्रभाव महत्वपूर्ण है। 2024 में, भारत ने अपने सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार, अमेरिका को 87.3 अरब डॉलर मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया। इसमें से लगभग 48-55 अरब डॉलर मूल्य की वस्तुएं सीधे तौर पर जोखिम में हैं। सबसे ज़्यादा मार श्रम-प्रधान, रोजगार सृजन वाले क्षेत्रों पर पड़ती है (चार्ट 1):	<ul style="list-style-type: none"> <li>सेवाएं और आईटी (वित्त वर्ष 2024-25 में \$387.5 बिलियन; अमेरिका को \$33.2 बिलियन); आईटी सेवाएं, बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं (बीएफएसआई) और परामर्श क्षेत्र मज़बूत बने हुए हैं, भारतीय कंपनियाँ फॉर्च्यून 500 कंपनियों को सशक्त बना रही हैं और अमेरिकी तकनीकी कंपनियाँ भारत में विस्तार कर रही हैं।</li> <li>ऊर्जा और स्वच्छ तकनीक: एलएनजी आयात, नवीकरणीय ऊर्जा साझेदारी और डीकार्बोनाइज़ेशन पर संयुक्त कार्य निरंतर गहरा रहे हैं।</li> <li>विमानन और एयरस्पेस: बोइंग विमान ऑर्डर, हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण और सीएनएस/एटीएम सहयोग अप्रभावित हैं।</li> <li>रक्षा: 2+2 वार्ता के तहत, सह-उत्पादन परियोजनाएँ, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और संयुक्त सैन्य अभ्यास संबंधों को मज़बूत कर रहे हैं।</li> <li>अंतरिक्ष और नवाचार: नासा-इसरो सहयोग और डिजिटल नवाचार साझेदारी सहयोग के भविष्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह दोहरी वास्तविकता - टैरिफ पारंपरिक निर्यात को नुकसान पहुँचा रहे हैं, जबकि सेवाएँ और रणनीतिक क्षेत्र फल-फूल रहे हैं - संबंधों की गहराई और विविधता को दर्शाती है।</li> </ul>
<b>संबंधों की असली मजबूती</b> सबसे मज़बूत आधार केवल व्यापार ही नहीं, बल्कि लोगों के बीच आपसी संबंध भी हैं। अगर व्यापार और कूटनीति "हाडिबियर" हैं, तो लोग "सॉफ्टवेयर" हैं जो साझेदारी को बनाए रखते हैं।	<ul style="list-style-type: none"> <li>प्रवासी: अमेरिका में 48 लाख की आबादी वाला भारतीय प्रवासी समुदाय चिकित्सा, कानून, व्यापार और राजनीति के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करता है। 150 से ज़्यादा भारतीय मूल के सीईओ अब वैश्विक निगमों का नेतृत्व कर रहे हैं और व्यापार प्रवाह के साथ-साथ बोर्डरूम को भी आकार दे रहे हैं।</li> <li>छात्र: अमेरिकी विश्वविद्यालयों में 2,00,000 से ज़्यादा भारतीय छात्रों के नामांकन के साथ, प्रतिभाओं की यह श्रृंखला दोनों देशों में नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को आकार दे रही है।</li> <li>पेशेवर: भारतीय आईटी इंजीनियर सिलिकॉन वैली को आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि अमेरिकी उद्यमी बेंगलुरु के स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र में निवेश कर रहे हैं।</li> <li>सांस्कृतिक आदान-प्रदान: भारतीय अमेरिकी कांग्रेस, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय नेतृत्व में सेवारत हैं, जबकि दीपावली जैसे त्यौहार व्हाइट हाउस में मनाए जाते हैं। ये दशकों से विकसित विश्वास-आधारित बंधन हैं, जो इस रिश्ते को संरचनात्मक और लचीला बनाते हैं।</li> </ul>
<b>रणनीतिक सहयोग</b> समान रूप से महत्वपूर्ण, अमेरिका-भारत साझेदारी व्यापार विवादों से कहीं आगे तक फैली हुई है।	<ul style="list-style-type: none"> <li>रक्षा और सुरक्षा: संयुक्त अभ्यास, खुफिया जानकारी साझा करना और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण बढ़ते रक्षा अभिसरण को उजागर करते हैं।</li> <li>विमानन: विमान बेड़े से लेकर हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण तक, भारत के विमानन उछाल में अमेरिका एक प्रमुख भागीदार है।</li> <li>जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा: दोनों देश नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और टिकाऊ ईंधन पर सहयोग कर रहे हैं।</li> <li>स्वास्थ्य सेवा और फार्मा: जेनेरिक दवाओं के अलावा, अमेरिकी कंपनियाँ अनुसंधान एवं विकास और नैदानिक परीक्षणों में भारतीय कंपनियों के साथ साझेदारी करती हैं।</li> <li>अंतरिक्ष: चंद्र मिशन से लेकर उच्चाह नैविगेशन तक, नासा-इसरो सहयोग फूटी से परे साझेदारी का विस्तार करता है।</li> </ul>
<b>संतुलित व्यापार जो टिकाऊ हो</b> फिर भी, अमेरिका-भारत संबंधों को केवल टैरिफ के नज़रिए से देखना एक भूल होगी। द्विपक्षीय व्यापार का एक बड़ा हिस्सा अप्रभावित रहता है — और फलता-फूलता रहता है (चार्ट 2):	भारत की प्रतिक्रिया सोची-समझी और रणनीतिक होनी चाहिए: अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और हिंद-प्रशांत क्षेत्र के बाजारों में विविधता लाना; आपूर्ति श्रृंखलाओं में नवाचार करके और मूल्य श्रृंखला में ऊपर उठकर घरेलू लचीलेपन को मज़बूत करें; और कूटनीति में डट रहे क्योंकि यही अक्सर असफलता और सफलता के बीच का अंतर पैदा करता है।
<b>दवाइयों</b> (लगभग 50 अरब डॉलर का उद्योग; 2025 की पहली छमाही में 3.7 अरब डॉलर का निर्यात): टैरिफ से मुक्त, भारत अमेरिका की जेनेरिक दवाओं की 40% माँग की आपूर्ति करता है।	शुल्क बाजारों को अस्त-व्यस्त कर सकते हैं, उद्योगों को अस्थिर कर सकते हैं और सुखियों में छा सकते हैं, लेकिन ये नियति निर्धारित नहीं करते। अमेरिका-भारत संबंध शीत युद्ध के संदेह, प्रतिबंधों और पिछले व्यापार विवादों से पहले भी बचे रहे हैं - और हर बार, ये और मज़बूत हुए हैं। गहरी सच्चाई यह है: विश्वास साझेदारी को परिभाषित करता है, शुल्क नहीं (तालिका 3)। और लोगों द्वारा निर्मित और रणनीति द्वारा मजबूत किया गया विश्वास यह सुनिश्चित करता है कि व्यापार में उथल-पुथल के बावजूद, संबंध स्थिर बने रहें।
	मेहनाज़ अंसारी एक पूर्व अमेरिकी सरकारी अधिकारी और वैश्विक व्यापार विशेषज्ञ और AeroStratgix की संस्थापक हैं।

## बिना किसी अनुवाद गलती वाला संस्करण फ्री में पढ़ने के लिए अभी 8168305050 पर संपर्क करें।

### महिला नशा उपयोगकर्ताओं को पहचानने की आवश्यकता

जम्मू-कश्मीर में नशा करने वालों के लिए कोई लिंग-संवेदनशील बुनियादी ढांचा नहीं है

जम्मू और कश्मीर (J&K) नशीली दवाओंके संकट की चपेट में है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के आंकड़ों से पता चला है कि 2022 में, जम्मू और कश्मीर में लगभग 1.08 लाख पुरुषों और 36,000 महिलाओं ने भांग का उपयोग करने की सूचना दी। लगभग 5.34 लाख पुरुषों और 8,000 महिलाओं ने ओपिओइड का सेवन किया, 1.6 लाख पुरुषों और 8,000 महिलाओं ने शामक दवाओं का इस्तेमाल किया, और 1.27 लाख पुरुष और 7,000 महिलाएं इनहेलेंट की आदी थीं।

पुरुषों की लत को लेकर चिंता बढ़ रही है, लेकिन महिलाओं की अनदेखी की जाती है। जबकि कई महिलाएं परिवार के पुरुष सदस्यों के बीच नशीली दवाओं के उपयोग का खामियाजा भुगतती हैं, उन्में से बहुत छोटा हिस्सा - 2023 में जम्मू और कश्मीर में नशीली दवाओं का उपयोग करने वालों का 7%, या लगभग 62,000व्यक्ति - विभिन्न कारणों से भी नशीली दवाओं की ओर मुड़ गए हैं बेरोजगारी का लंबा दौर; वैवहिक समस्याएं; और लिंग-आधारित दबाव। कुछ महिलाओं का कथित तौर पर नशीली दवाओ की तस्करी के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, कभी-कभी यौन शोषण भी। कुछ को उनके पुरुष मित्रों और परिवार के सदस्यों द्वारा भी नशीली दवाओ से परिचित कराया जाता है।

चूँकि महिलाओं को अपने परिवारों के लिए शर्म और अपमान का कारण माना जाता है इसलिए उन्में से कई को उनके समुदायों में अलग-थलग कर दिया जाता है। इसके अलावा, महिला नशीली दवाओं का उपयोग करने वालों की सहायता के लिए कोई लैंगिक-संवेदनशील बुनियादी ढाँचा नहीं है। मंत्रालय के अनुसार, भारत भर में 46 व्यसन उपचार केंद्रों में से केवल 10 जम्मू-कश्मीर में हैं, और देश भर के 340 पुनर्वास केंद्रों में से, जम्मू-कश्मीर में केवल एक ही ऐसा केंद्र है। इस क्षेत्र में केवल महिलाओं के लिए कोई पुनर्वास केंद्र नहीं है। महिला परामर्शदाताओं की संख्या बहुत कम है - यह संकट विशेष रूप से गंभीर है जब हम दुर्व्यवहार की कहानियों पर विचार करते हैं। महिलाओं के लिए नशे की लत के बारे में खुलकर बात करने के लिए कोई सार्वजनिक स्थान भी नहीं है। फिर महिलाएं मदद कहाँ से लेगी या एक-दूसरे के साथ अपनी कहानियाँ कहाँ साझा करेंगी?

नशीली दवाओं का उपयोग करने से जुड़ी शर्म, मादक द्रव्यों के सेवन के मनोवैज्ञानिक प्रभाव से और भी बढ़ जाती है, जिससे महिलाएं अदृश्य हो जाती हैं। सामाजिक कलंक और उदासीनव्यवस्था के कारण उनके आघात का इलाज नहीं हो पाता। यह उपेक्षा आकस्मिक नहीं है; यह महिलाओं को व्यसन संकट का हिस्सा मानने और उपचार व पुनर्वास के दौरान उनकी अलग लिंग-आधारित आवश्यकताओं को मानने में संरचनात्मक विफलता को दर्शाती है।

युवाओं, विशेषकर महिलाओं में हेरोइन की लत का बढ़ता चलन उत्तर भारत के राज्यों और सीमा पार से नशीली दवाओकी निर्बाध आपूर्ति के कारण संभव हुआ है। ड्रग माफियाओं का स्थानीय डीलरों के साथ घनिष्ठ संबंध है, जिससे घाटी में नशेडियों तक नशीली दवाओं का आसानी से प्रवाह हो रहा है। सरकार उधमपुर जैसेस्थानों पर राजमार्गों पर निगरानी बढ़ाकर इस गठजोड़ को तोड़ सकती है।

सरकार ने क्षेत्र में नशीली दवाओं की आपूर्ति के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए निवारक उपाय केरूप में नशीली दवाओं के तस्करों की करोड़ों रुपये की संपत्तियां जब्त की हैं। हालाँकि, नशीली दवाओं के आपूर्तिकर्ताओं की संपत्तियों को जब्त करने से वे हमेशा के लिए अपराधी बने रह सकते हैं। हालाँकि सरकार के लिए तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना अनिवार्य है, लेकिन उनके घरों सहित उनकी संपत्तियों को जब्त करने से उनके सामाजिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। पुनर्वास करुणामय और मानवीय देखभाल पर आधारित होना चाहिए।

इस क्षेत्र की अनूठी विशेषता ने महिलाओं की स्वायत्तता को लंबे समय से दक्किनार कर दिया है। महिलाओं की नशीली दवाओं की लत से जुड़े कलंक ने उनकी पीड़ा को और गहरा कर दिया है।

हमें ऐसे जन जागरूकता अभियानों की आवश्यकता है जो नशीली दवाओं की लत को एक नैतिक विफलता के बजाय एक बीमारी के रूप में प्रस्तुत करें - विशेष रूप से एक पुरानी, बार-बार होने वाली मस्तिष्क संबंधी बीमारी के रूप में। गाँवों में महिला सहायता समूहों का निर्माण कलंक को विश्वास और एकजुटता से बदलनेमें मदद कर सकता है। अधिक लिंग-संवेदनशील बुनियादी ढाँचा समय की माँग है। जम्मू-कश्मीर को ऐसे केंद्रों की आवश्यकता है जहाँ महिला उपयोगकर्ताओं के साथ गोपनीयता और सहानुभूति के साथ व्यवहार किया जाए ताकि अधिक महिलाएं इलाज के लिए आगे आएँ। पुनर्वास सुविधाओं को देखभाल और पुनर्वास के प्रभावी केंद्र बनने के लिए उचित धन और कर्मचारियों की आवश्यकता है।

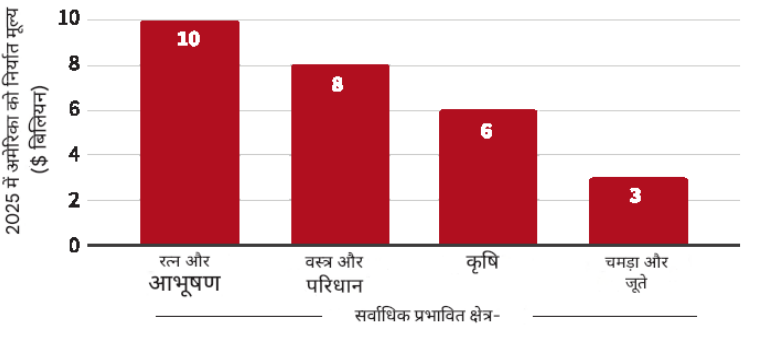
लेकिन यह सब संभव हो सके, इसके लिए यह ज़रूरी है कि जम्मू-कश्मीर सरकार सबसे पहले यहस्वीकार करे कि नशीली दवाओं की लत एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति है जिसके लिए सरकार और समुदाय दोनों की भागीदारी आवश्यक है। और यह कि महिला नशीली दवाओं का सेवन करने वालों को उचित और अलग पुनर्वास की आवश्यकता है, जिसमें चिकित्सा, परामर्श और ठीक होने और एक सामन्य और सम्मानजनक जीवन जीने का उचित अवसर शामिल हो।

*बिलाल गनी, राजकीय डिग्री कॉलेज, राजनीति विज्ञान संकाय के अध्यक्ष हैं।*

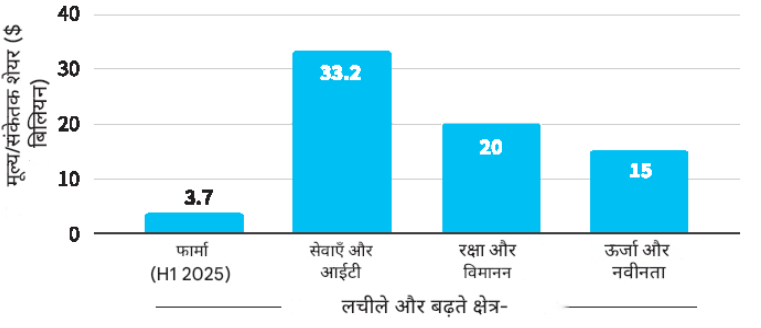
*बीरवाह, जम्मू और कश्मीर*



चार्ट 1: प्रमुख निर्यात क्षेत्र जो टैरिफ से प्रभावित होंगे



चार्ट 2: टैरिफ से सीधे प्रभावित न होने वाले प्रमुख क्षेत्रों का मूल्य



तालिका 3: टैरिफ बनाम ट्रस्ट

धनिक	मान
जोखिम में निर्यात (टैरिफ)	<b>\$48B</b>
अमेरिका में भारतीय प्रवासी	<b>4.8M</b>
अमेरिका में भारतीय छात्र	<b>200K</b>

टैरिफ बाज़ारों को अस्त-व्यस्त कर सकते हैं, उद्योगों को अस्थिर कर सकते हैं और सुखियों में छा सकते हैं, लेकिन ये नियति निर्धारित नहीं करते। अमेरिका-भारत संबंध पहले भी शीत युद्ध के संदेह, प्रतिबंधों और पिछले व्यापार विवादों से बच निकले हैं - और हर बार, ये और भी मज़बूत हुए हैं।